Demand of Gujarat for funds under EAS

2821. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the demand of Gujarat for funds under Employment Assurance Scheme (EAS) for manual work during the lean agricultural seasons in rural areas of the State during the last three years, year-wise;

(b) whether the demand of the State was fully met;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the remedial measures proposed to be taken by Government to meet the demand of the State?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) Though Employment Assurance Scheme (EAS) is a demand driven scheme, yet first instalment of EAS during 1993-94, 1994-95 and 1995-96 was released to all the States on ad-hoc basis. The funds released to Gujarat for the last three years are as follows:—

(Rs. in lakhs)

Year	Central funds released
1993-94	485.00
1994-95	3580.00
1995-96	6970.00

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Doe not arise.

मधुबनी,बिहार में एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा कपार्ट की धनराशि का दुरूपयोग

2822. **श्री राम देव भंडारी**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मधुबनी जिले में सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र पथराही,झंझारपुर(आर.एस.) के कपार्ट द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) उक्त संगठन के विरूद्व धन का दुरूपयोग करने के लिये किस-किस प्रकार की जांच कराई गई है;

(ग) क्या दो सदस्यीय जांच समिति ने धनराशि के दुरूपयोग और बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के बारे में फरवरी में प्रतिवेदन दिया था;

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ड) उपरोक्त संगठन को काली सूची में न डालने,धनराशि देना बन्द न करने और उनसे धनराशि वापस न कराने और इसके विरूद्व कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराए जाने के क्या कारण है; और

(च) क्या सरकार ऐसी कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) कपार्ट द्वारा बिहार के मधुबनी जिले में सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्री पथराही,झंझारपुर को 91.18 लाख रूपए दिए गये हैं।

(ख) से (घ) एक शिकायत के आधार पर तीन परियोजना मूल्यांकनकर्त्ताओं की एक दल भेज कर कपार्ट ने शुरू में सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र की कार्य प्रणाली की जांच करवाई थीं । इस दल के निष्कर्षो के आधार पर इस संगठन द्वारा रोहतास एंव पलामू जिले में पेयजल परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में दो परियोजा मूल्यांकनकर्त्ताओं के एक संयुक्त दल द्वारा विस्तृत जांच की गई है । कपार्ट को जनवरी/फरवरी 97 में प्राप्त दो सदस्यों के दल की रिपोर्ट में इस संगठन द्वारा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनुपयुक्त निष्पादन,जागरूकता एंव प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाना,घटिया किस्म के हार्डवेयर का प्रयोग करना,गलत रिपोर्ट देना आदि जैसी कुछ एक कमियों/ खामियों के बारे में बताया गया है इस दल ने यह भी सिफारिश की कि इस संगठन से 9.74 लाख रूपए की वसूली की जाए।

(ड़) और (च) कपार्ट ने इस संगठन को आगे धन देना बन्द कर दिया है । कपार्ट द्वारा दो सदस्यीय दल की रिपोर्ट की जांच भी की जा रही है,जिससे अगली कार्रवाही का निर्धारण किया जा सके।